उसमें आपके कोई और सुझाव होंगे जो इस कानून को और अच्छा व बेहतर बना सकेंगे सरकार उनका स्वागत करेगी और उनको शामिल करेगी । इस मामले में कोई भी सुझाव, कोई भी व्यवस्था जो मेरे सामने रखी जाएंगी जिससे बालक और बालिका के बीच में यह अंतर समाप्त हो मैं उसका खुले दिल से स्वागत करूंगा और पूरी मदद करूंगा ।

Objectives of National Education Policy

*65. DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the trend of public expenditure on education expressed as a percentage of GDP and total public expenditure since 1990; and

(b) whether this trend is consistent with the resource requirements for meeting the National Education Policy objectives?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

A Statement-I indicating the total public expenditure and expenditure on education and other Departments as percentage of GDP from 1990-91 to 2002-03 is enclosed. (See below)

From the statement it may be observed that the total expenditure on education has increased from Rs. 19615.85 crore in 1990-91 to Rs. 88919.00 crore in 2002-03 (Budget Estimate) to meet the requirement of various educational schemes/projects.

Statement-I

Objectives of National Education Policy

(Rs. in crore)

Year	Total Public Expenditure	Expenditure* On Education & other Deptts.	Expenditure On Education &other Deptts. as % age of GDP
1	2	3	4
1990-91	146711.53	19615.85	3.84
1991-92	170370.38	22393.69	3.80
1992-93	190327.49	25030.30	3.72

1	2	3	4
1993-94	218535.15	28729.69	3.62
1994-95	251691.92	32606.22	3.56
1995-96	286194.55	38178.09	3.56
1996-97	329389.92	43896.48	3.53
1997-98	370838.48	48552.14	3.49
1998-99	439768.12	61578.91	3.85
1999-2000	512519.33	74816.09	4.25
2000-01	572160.14	82486.48	4.30
2001-02 (RE)	639048.06	84179.46	4.02
2002-03 (BE)	699098.41	88919.00	3.98

RE = Revised Estimates

BE = Budgeted Expenditure

* This does not include expenditure on Research and Development by various Departments *e.g.* Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Department of Ocean Development, Defence Research and Development Organisation, Department of Atomic Energy, Department of Space etc. as also the extramural support to academic sector by these Departments.

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, I had asked the hon. Minister to indicate the public expenditure on education as a percentage of GDP of the country and as a percentage also of the total public expenditure. Unfortunately, one of the question has not been answered. I have no figures, which tell us what is happening to public expenditure on education as a proportion or as a percentage of the total expenditure.

Whatever data the hon. Minister has given, I think, it gives rise to a serious questioning about the Government's commitment to devote adequate resources for education because, in the last three years, the figures for which have been given, show that public expenditure on education, as percentage of our GDP, is going down. And, if the hon. Minister had given public expenditure on education as a proportion of the total public expenditure, that would have also established the same thing. This causes a serious doubt about the Government's commitment to the educational objectives of the National Education Policy.

डा. मुरल मनोहर जोशी : श्रीमन्, यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ उसमें आपको ह्रास दिखाई देगा। जो इंडीकेटर्ज हैं वे बिल्कुल ठीक हैं और वह जानकारी भी मैं आपको भेज दूंगा। मेरे पास वह जानकारी उपलब्ध है और उसे मैं आपको भिजवा दूंगा। अब जो बुनियादी बात डा. मनमोहन सिहं जी ने उठाई है, जोकि महत्वपूर्ण हैं, वह यह है कि शिक्षा के ऊपर खर्चा हमारे सकल घरेलू उत्पाद के और सारे सरकारी विभागों का तुलना में कितना हो रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ मामलों में राज्य सरकारों की तरफ से चूंकि पूरे आंकडे मिल नहीं पाते हैं तो हम यह कहने की स्थिति में आज नही हैं कि उनके यहां कितनी-कितनी घटोत्तरी हुई है। लेकिन जो भी हम देख रहे हैं और जो हमारे पास आंकडे उपलब्ध है, उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि हमारी केन्द्र की जो राशि है , वह निरंतर इसमें बढ़ रही है। वर्ष 1990-91 में यह 1643 करोड़ थी, उसके बाद यह 1996-97 में 3672 करोड़ हो गई, वर्ष 1997-98 में यह 4623 करोड़ थी और 1998-99 में यह 6323 करोड़ हो गई। उसके बाद अब यह 9791 करोड़ हैं। इस प्रकार यह हर साल बढती चली जा रही है? जहां तक केन्द्र का सवाल है, तो यह राशि बराबर बढ़ती जा रही है। जहां तक राज्यों के अदंर की बात है, तो कुछ-कुछ राज्यों मे कमी हुई है। वह कितनी कमी हुई है, इसका आकलन लगाने में आप भी जानते हैं, क्योकि आप भी वित्त मंत्री रहे हैं, कि इसमें कितनी कठिनाई होती है, लेकिन इस बात की हम बहुत गहराई से छान-बीन कर रहे हैं कि शिक्षा के मामले में किस सैक्टर में कहां कमी हो रही है और उस कमी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। बराबर राज्य सरकारों से हम संपर्क रख रहे हैं कि वे इस चीज से बराबर हमें अवगत कराते रहें। हम यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए।

अब मैं देखता हूं कि आपने जो सवाल किया है , उसके बारे में मैं कोई तत्काल जानकारी आपको दे सकूं। परसेंटेज आफॅ जी.डी.पी. एक्सपेंडीचर ऑन एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें भी वही स्थिति है। 3.37 तब से चल रहा था और फिर यह घटते-घटते 2.96 पर आ गया और अब यह बढ़कर 3.28 हो गया है तो वह भी वहां 3.9 से 8 आता है और यहां 3.28 आता है, क्योंकि सरकारी खर्चे बढ़ रहे हैं इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकार के और बहुत से खर्चे फिफ्थ पे कमीशन की वजह से जो बढे हैं , वे खर्चे उधर बढे हैं। नान-प्लान खर्चो मे जो वृद्धि हुई है उसके कारण से यहां कुछ घटोत्तरी हुई है, लेकिन दोनों मे ट्रेड वही है। अगर आप देंखेंगे तो पायेंगे कि ट्रेंड वही है और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अपने बुनियादी बात जो उठाई है वह सच है कि शिक्षा के लिए जिस तेजी से खर्चा होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ, लेकिन उस रफ्तार में वृद्धि हुई है और उससे हम सहमत हैं। इसके लिए सबके सहयोग से बराबर हम कोशिश कर रहे हैं,क्योंकि जनता की तरफ से भी दबाव पड रहा है। इसलिए बराबर हम उसके लिए प्रयत्नशील है। हमारे जो आंतरिक साधन है, उनको भी हम जुटा रहे हैं और जो बाह्य साधन हैं उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इससे हम सहमत हैं।

DR. MAHMOHAN SINGH: Sir, I do not want to join the issue with the hon. Minister. The figures that he himself has supplied show that in the year 1999-2000, the total public expenditure on education, as a proportion to our GDP, was 4.25 per cent. The latest year- for which the hon. Minister provided the figures—is the year 2002-03. This percentage has fallen to less than 4 per cent. That cannot be considered as a healthy development, considering all the ambitious objectives that the country has accepted in terms of the National Education Policy.

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, इसमें यह बात ध्यान देनी चाहिए कि वर्ष 1999-2000 में और 2001 में जो वृद्धि हुई है, वह मूलतः फिफ्थ पे कमीशन के कारण हुई है । अगर आप देखेंगे तो उसके पहले यह 3.8 परसेंट है और आज वह बढ़कर 3.98 परसेंट हो गई है । इसलिए आप यह मत समझिए कि शिक्षा में हमारा जो फंडामेंटल इनवेस्टमेंट है, उसमें कमी हो रही है। वह तो पे –स्केल्स के सारे एरियर्स दिए गए, उस वजह से ...(**व्यवधान**)...

श्री ललितभाई मेहता : सभापति जी, मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर सकल घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत बढ जाता है, अगर यह 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के करीबन हो जाता है तो क्या उसके कारण शिक्षा का विकास हो जाएगा ? महोदय, शिक्षा की जो हमारी परिकल्पना है, उस के अनुसार चरित्र के आधार पर , ज्ञान के आधार पर और संस्कृति के आधार पर बालक/बालिकाओं का विकास हो तो क्या खर्च बढ़ाने से वैसा विकास हो सकता है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। विकास हो सकता है । क्योंकि शिक्षा पर खर्च बढने से शिक्षा की सुविधाएं , शिक्षा का वातावरण, शिक्षकों की क्वालिटी और पुस्तकों की क्वालिटी- इन सब में परिवर्तन आता है। इसलिए इन दोनों का एक संबंध है । ऐसा नही है कि इन का बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। शिक्षा पर व्यय और शिक्षा की क्वालिटी – इन दोनों मे संबंध है और इसलिए उस पर असर पड़ता हैं।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I think, what is very significant is the other part of the question, which Dr. Manmohan Singhji has put, "Whether this trend is consistent with the resource requirements for meeting the National Education Objectives?" For the last three years, we have been hearing the Government, and Dr. Joshi, in particular, shouting from roof top that they have taken unprecedented initiatives in terms of constitutional amendments and all that. When I see the figures, I don't know, how does the BERE become comparable. I mean, they should have been consistent. But anyway, the process of reduction in expenditure, as

percentage of the GDP, is exactly timed with all those initiatives that had been taken. When-the entire Parliament is supporting the Government in terms of passing constitutional amendments, the expenditures should get matched with the Budget figures also, because it is we the Parliament, who are passing the constitutional amendments. But there is a complete reversal. So, the hyperboles used on all these educational. *....(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please come to the question.

SHRI NILOTPAL BASU: How will they match, Sir?

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, जो बजट पार्लियामेट ने पास किया है , हम उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसलिए अभी तक तो मैं यही कह सकता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत और इन सबकी शुरूआत का यह पहला साल है । अब जो बजट आपने एलोकेट किया है, उसी के अतंर्गत हमें राशियां मिल रही हैं और हम उसी से काम कर रहे हैं । ....(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु : आप लोगों के कहने पर किया है न।

डा. मुरली मनोहर जोशी : हमारे कहने पर आपने दिया है। जो पार्लियामेंट ने पास किया है, वह **हम** को मिल रहा है।

श्री सभापति : जो आप ने बजट बनाया है, वह पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, लेकिन सदन की इच्छा है कि बजट में शिक्षा के लिए और ज्यादा प्रावधान होना चाहिए ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, हम उससे सहमत हैं और मै तो बराबर उसके लिए कह रहा हूं।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, you will recall that in 1995, when Shri P.V. Narsimha Rao was the Prirne Minister, there was an EFA meeting. In that meeting, I distinctly recall, a commitment was made that the expenditure on education would go up to 6 per cent of the GDP. Unless it does go up to 6 per cent of the GDP, we will not be able to either meet any of the norms that have been laid down by the UNESCO, or be able to give our people the sort of education that they require. Now, it is for the Government to see that the Plans and the Budgets come up to that figure of 6 per cent. It is really stunning that even after nine years of that commitment we are still around four per cent. Will the Minister be pleased to tell the House, whether he will ensure that in the next Budget and in the current Plan, we do substantially increase our expenditure on education?

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, एक बात ध्यान देने की हैं कि यह केवल सरकारी निवेश है । इसके अलावा निजी निवेश श्री शिक्षा में बहुत है और वह निवेश मिलाकर आप 7 प्रतिशत तक पहुंचते हैं । श्रीमन्, मैं यहा उस बात को नहीं उठाना चाहता, लेकिन मेरी यह निश्चित धारणा है कि सरकारी निवेश 6 प्रतिशत होना चाहिए । जो वर्ष 1995 का कमिटमेंट हैं उस में सरकारी और गैर-सरकारी का अंतर नहीं किया गया है । आज हम चाहते हैं कि पब्लिक इनवेस्टमेंट 6 प्रतिशत हो, अगर और ज्यादा हो तो अच्छा है क्योकि दुनिया के तमाम विकसित देशों में से कुछ में यह प्रतिशत 9 से 11 प्रतिशत तक गया हुआ है । अभी तो हम सरकारी और गैर-सरकारी मिलाकर, यह 6 या 6.5 या 7 के नजदीक पहुंच पाए हैं । इसको तीन, चार प्रतिशत और बढाने की आवश्यकता है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं ।

श्री नीलोत्पल बसु : सर, इनके जवाब में इनअक्योरेसी है । वह तो पहले ही तय हुआ था टर्म्स एंड ओब्जेक्टिव्स के समय कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट 6 परसेंट जी.डी.पी. का होगा । यही तय हुआ था, पब्लिक-प्राइवेट मिलाकर नहीं ।

श्री सभापति : वह तो मंत्री महोदय ने बता दिया । नैक्स्ट क्वेश्चन ।

Mid-Day Meal Scheme

*66. SHRIMATI AMBIKA SONI:
DR. T. SUBBARAMI REDDY: †

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Mid-Day Meal Scheme has been expanded further throughout the country;

(b) if so, whether many opposition parties have also urged Centre to expand Mid-Day Meal Scheme;

(c) whether mid-day meal supplied in Delhi and other places have been found affecting children instead of helping them;

(d) if so, whether Centre has been informed that in number of States, after mid-day meal were supplied, number of children has been forced to go to hospitals;

(e) the total number of students who were affected due to this; and

(f) the steps Government propose to take, to prevent such incidents in future?

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri T. Subbarami Reddy.-